साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 12-18 अगस्त 2024 वर्ष-10, अंक-17

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8, मूल्यः- 2 रुपए

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 500 किसान समूह बनेंगे

अच्छे दिन! किसानों को तीन साल तक मिलेंगे पांच-पांच हजार

किसानों को प्रति हेक्टेयर 5000 तीन साल तक मिलेंगे

भोपाल। जागत गांव हमार

खेती की लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में समूह बनाकर जैविक खेती करवाई जाएगी। पांच-पांच सौ किसानों के समूह बनाए जाएंगे। इन्हें खेती करने के तौर-तरीके सिखाने के साथ उपज की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार आउटसोर्स एजेंसी का चयन करेगी। इसका जिम्मा किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ उपज की ब्रिकी का प्रबंध करना होगा। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति हेक्टेयर पांच-पांच हजार तीन वर्ष तक दिए जाएंगे। इन्हें कहीं से भी सामग्री लेने की छूट रहेगी। तीन वर्ष तक किसान द्वारा की जाने वाली खेती का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। जैविक उत्पाद का प्रमाणीकरण भी करवाया जाएगा, ताकि उपज का अच्छा मूल्य मिले। उवर्रक और रसायनिक पदार्थों के उपयोग से खेती की लागत बढ़ती जा रही है। मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी प्रभावित हो रही है। अत्याधिक मात्रा में खाद और कीटनाशकों के उपयोग से उपज की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है, इसलिए सरकार भी जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है।

परंपरागत खेती पर जोर- भारत सरकार ने मृदा उर्वरता में सुधार एवं स्वास्थ्यप्रद कृषि उत्पाद के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि किसानों का समूह ऐसे बनाया जाएगा जिससे 20 हेक्टेयर का क्षेत्र निर्मित हो सके। 10 से 25 समूहों को मिलाकर एक क्लस्टर बनेगा, जो अधिकतम 500 हेक्टेयर का होगा।

- » प्रमाणीकरण की जिम्मेदारी आउटसोर्स एजेंसी की होगी
- » किसान की भूमि की पूरी रिकॉर्डिंग और निगरानी की जाएगी
- » महाकोशल और निमाड़ अंचल में फोकस करेगी सरकार
- » किसान को कहीं से भी खेती की सामग्री लेने की रहेगी छूट

दो हेक्टयर भूमि तक लाभ

किसान के पास उपलब्ध भूमि में से अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि तक के लिए लाभ दिया जाएगा। सचिव कृषि एम सेलवेंद्रन का कहना है कि योजना में लघु और सीमान्त किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्षेत्र भी ऐसे चयनित किए जाएंगे, जहां परंपरागत तरीकों से खेती की जाती है और उर्वरकों व रसायनों का कम प्रयोग किया जाता है।

कब क्या करना है यह भी बताएंगे

जैविक खेती कार्यक्रम के संचालक के लिए एक क्लस्टर समन्वयक नियुक्त किया जाएगा। 100 हेक्टेयर क्षेत्र वाले पांच समूहों के लिए प्रेरक रहेगा। ये जैविक खेती, जैविक प्रमाणीकरण, बायो इनपुट निर्माण, वेल्यू एडिशन एवं मार्केटिंग संबंधित प्रशिक्षण दिलवाएंगे। इसके लिए कृषि विभाग, अशासकीय संस्थाओं के विशषज्ञों का भी सहयोग आवश्यक रूप से लिया जाएगा।

लगातार रखी जाएगी नजर

जैविक खेती के लिए चयनित किसानों पर लगातार नजर रखी जाएगी। प्रत्येक फार्म हिस्ट्री संधारित की जाएगी। आंतरिक निरीक्षण होगा और उपज का मूल्यांकन होगा। साथ ही जैविक उत्पादों के ब्रांड निर्माण के लिए व्यापक विपणन कार्ययोजना तैयार की जाएगी। विशिष्ट बाजारों में स्टाल लगाने और खुदरा व्यापारी के साथ सीधे बाजार जुड़ाव की सुविधा के लिए आयोजन किए जाएंगे।

जैविक उत्पाद में मप्र की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत

देश के कुल जैविक उत्पाद में मध्य प्रदेश का हिस्सा सर्वाधिक 40 प्रतिशत है। लगभग 17 लाख हेक्टेयर में एक लाख से अधिक किसान जैविक खेती कर रहे हैं। इसमें सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, तुअर, उड़द, बाजरा, रामतिल, मूंग, कपास, कोदो-कुटकी आदि फसल उपज शामिल है।

सरकार की पहल

- » जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अब सेवा प्रदाता का चयन करेगी।
- » ये किसानों को एकत्र करके समूह व क्लस्टर का निर्माण करेंगे।
- » किसानों को कृषक उत्पादक समूह या सहकारी समितियों का सदस्य बनवाया जाएगा।
- » किसानों को क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा।
- » उत्पाद एकत्रीकरण, पैकिंग, विपणन, लोगो तैयार करने, परिवहन आदि की व्यवस्था भी सेवा प्रदाता करेंगे।
- » जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण करने का जिम्मा भी आउटसोर्स एजेंसी का रहेगा।

प्रदेश में यहां होती है अधिक जैविक खेती

मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, उमरिया, दमोह, सागर, आलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, सीहोर, श्योपुर और भोपाल।

सरकार की तैयारी: योजना में 200 करोड़ का खर्च आएगा

दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए बोनस

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार दुग्ध उत्पादकों को पांच रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देगी। यह राशि दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को दी जाएगी। इसी माह कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी है। झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और असम में पहले से किसानों को पांच रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हालांकि, सरकार की इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 प्रतिशत दुग्ध उत्पादकों को ही लाभ मिल पाएगा। कारण, इतने ही किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से जुड़े हैं। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध संग्रहीत किया जाता है, जिस पर सहायता दी जाएगी। यही दूध प्रदेश के छह सहकारी दुग्ध संघों में पहुंचता है जहां से बिक्री के लिए भेजा जाता है।

सीएम ने देखा था अमूल मॉडल

दरअसल, राज्य सरकार वर्तमान वर्ष को गोरक्षा वर्ष के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में गोपालकों के लिए यह सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसी वर्ष जनवरी में अहमदाबाद में अमूल का मॉडल देखा था। इसके अनुरूप उत्पादन बढ़ाने पर जोर है।

राज्य सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी। इसका फायदा सहकारी दुग्ध समिति से जुड़े किसानों को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सहकारी समिति से किसानों को जोड़ने के लिए भी सहकारी दुग्ध संघ के सेंटर बढ़ाए जाएंगे। इसको लेकर अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।

लखन पटेल, पशुपालन मंत्री

किसानों को सहायता देने में प्रतिवर्ष लगभग दो सौ करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एक से दो माह में कैबिनेट के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सरकार की इस पहल से पशु पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उनकी आय भी बढ़ेगी।

गुलशन बामरा, पीएस, पशुपालन विभाग

आईएएस अंशुल गुप्ता बने जनसंपर्क संचालक

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आईएएस अफसरों के स्थानांतरण आदेश में जहां कई वरिष्ठ आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है। वहीं जिलों में पदस्थ कई कलेक्टरों के भी स्थानांतरण किए गए हैं। स्थानांतरण सूची में आईएएस अफसर अंशुल गुप्ता को जनसंपर्क संचालनालय मप्र का संचालक बनाया गया है। अंशुल गुप्ता इसके पहले उपसचिव मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम सहित अन्य कई विभाग के कार्यपालक संचालक रहे हैं। अंशुल गुप्ता सन

2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे उज्जैन के नगर निगम आयुक्त रह चुके हैं। इसके पहले वह उमरिया जिले के जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर भी रहे हैं। इसके अलावा श्री गुप्ता इंदौर के महू और धार जिले के कुक्षी में एसडीएम भी रह चुके हैं।

-प्रदेश के संतरे-केले को सरकार दिलाएगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान

मध्यप्रदेश सरकार बनाएगी मसाला मंडी

भोपाल। जागत गांव हमार

उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से किसान और उद्योगपति दोनों लाभान्वित होंगे। इनके माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में उद्यमिता और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अत: उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के परस्पर समन्वय से रोजगार के अवसरों व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस दिशा में सार्थक प्रयास किए गए हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ उनके परिवारों को जोड़ने के लिए स्व-सहायता समूहों का भी गठन किया जाए। प्रदेश में संभाग स्तर पर हाईटेक नर्सरियां स्थापित कर आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का बजट बढ़ाकर बाजार की मांग के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाएं। इस दिशा में हार्टिकल्चर प्रमोशन एजेंसी स्थापित कर समय-सीमा व रोडमैप निर्धारित करते हुए कार्य किया जाए। बैठक में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

» मुख्यमंत्री मोहन ने की उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा

» उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण से किसान-उद्योगपति होंगे लाभान्वित

» रोजगार के अवसरों और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी

अंतरराष्ट्रीय पहचान के लिए हों प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश मसालों की पृथक मंडी विकसित की जाए। मसालों की खेती का अन्य जिलों में भी विस्तार किया जाए। प्रदेश में बड़े पैमाने पर फल, सब्जी, मसालों आदि का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के संतरा, केला, पान, लहसुन आदि की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।

फलदार पौधे लगाएं

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जारी पौधारोपण अभियान में फलदार पौधे लगाने को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में फल, सब्जियों, औषधीय पौधों आदि के आर्गेनिक प्रोडक्शन, उनके डिहाइड्रेशन प्लांट व गामा रेडिएशन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए।

बेहतर कार्य पर मिलेगा सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि किसान को उसकी मेहनत और निवेश का पूरा लाभ मिले व परिस्थितिवश किसी भी स्थिति में उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। आधुनिकतम तकनीक और शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जाएं। बेहतर कार्य करने वालों को शासकीय कार्यक्रमों में सम्मानित करें, जिससे अन्य किसान व उद्यमी प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन भूमि पर न्यायालय में याचिका दायर

इंदौर-जलबलपुर में सरकार अब बनाएगी सिटी फारेस्ट

उज्जैन की मिलों पर व्यवसायिक गतिविधियों की योजना विकसित

भोपाल। जागत गांव हमार

इंदौर शहरी क्षेत्र में बंद मिलों की जमीनों का उपयोग शहर हित में किया जाना है। मालवा मिल की जमीन के एक हिस्से में सिटी फारेस्ट विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। नगर वन विकास करने की योजना के तहत इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा इंदौर और जबलपुर शहरी क्षेत्र में नगर वन (सिटी फारेस्ट) विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से तेजी से कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में नगर वन विकसित करने संबंधी प्रस्ताव रखा गया है।

लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन से इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं बुरहानपुर जिले की बंद मिलों की भूमि को पुन: राज्य शासन के पक्ष में बंदोबस्त (वैष्ठित) कर लिया गया है। इसके विरुद्ध नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ने इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल की भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। संबंधित जिलों के कलेक्टरों से समन्वय स्थापित कर विभाग द्वारा इन भूमि प्रकरणों के जल्द से जल्द निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

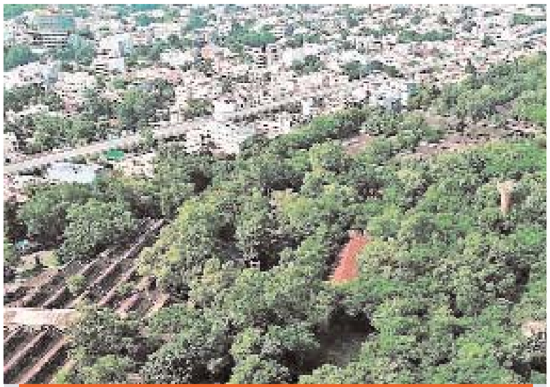

यहां भी बन रही योजना

उज्जैन की विनोद मिल के शेष पार्सलों पर व्यवसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिये विभागीय योजना तैयार की जा रही है। उज्जैन की हीरा मिल का समुचित प्रबंधन भी विभागीय तौर पर किया जा रहा है। लोक परिसम्पत्ति विभाग द्वारा जबलपुर शहरी क्षेत्र में बीएसएनएल द्वारा अधिग्रहित भूमि को पुन: राज्य शासन के पक्ष में बंदोबस्त (वैष्ठित) कर लिया गया है। अब यहां सिटी फारेस्ट के लिए जरूरी विकास के मद्देनजर समुचित प्रबंधन एवं व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

कल्याण मिल का होगा प्रबंध

इंदौर जिले में स्थित यूनाइटेड मालवा मिल का एक प्रमुख भाग प्रबंधन की मंशा से नगर वन (सिटी फारेस्ट) के रूप में विकसित करने के लिये बेहद उपयुक्त पाया गया है। इस विकास प्रस्ताव पर विभागीय योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है एवं कल्याण मिल का उचित रूप से प्रबंधन किया जा रहा है।

16 जिलों के विकास प्रस्ताव तैयार

लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा जिलों में मौजूद आधारभूत संरचनाओं को और अधिक सुदृढ़ कर इन्हें नई जरूरत अनुसार विकसित करने के लिए गत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में 20 जिलों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कुल 126 करोड़ 79 लाख वितरित किए गए। जारी वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना में 16 जिलों से पात्रतानुसार 65 करोड़ 49 लाख के विकास प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए भी विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

सेल्फी लेने आ रहे लोग, 5 साल पहले लगाए थे पौधे

किसान के खेत में सागौन के पेड़ बने आकर्षण का केंद्र

दमोह। जागत गांव हमार

दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक के पांजी गांव निवासी किसान नरेंद्र लोधी का पर्यावरण के प्रति ऐसा अनोखा प्रेम है कि आज वह अन्य किसानों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। उन्होंने अपने खेत की मेड पर सागौन के पौधे रोपे थे, जिसमें से 400 पौधे आज पेड़ बन गए हैं। स्थानीय लोग इतनी संख्या में इन पेड़ों को देखकर रोमांचित हो रहे हैं और यहां सेल्फी लेने आ रहे हैं। नरेंद्र बताते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की तरह इन पौधों की परवरिश की है, जिसका नतीजा सभी के सामने है। किसान नरेंद्र लोधी की खेती खेरा गांव में है, जहां धान की फसल बोई गई है। यहां खेतों की मेड़ों पर हरियाली के रूप में सैकड़ों कीमती सागौन के पेड़ लगे हुए हैं जो अपने आप में सुंदरता बिखेर रहे हैं। लगातार हुई बारिश के बाद खेत पानी से भर गया है और उसके चारों ओर लगे सागौन के हरे भरे पेड़ देखकर लोग यहां आकर सेल्फी और फोटो ले रहे हैं।

600 में से 400 जीवित

नरेंद्र लोधी के खेत देखकर सभी का मन अब खेतों की मेड पर पौधरोपण करने का हो रहा है। कई किसान इस तरह पौधे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र लोधी ने बताया कि खेत की मेड़ों पर उन्होंने पांच वर्ष पहले सागौन के 600 पौधे सागौन के रोपित किए थे, जिनमें से 400 पौधे जीवित हैं, जो अब पेड़ बन गए हैं। यह पेड़ बेसकीमती होने के साथ ही गर्मियों में छाव का भी काम करते हैं।

नहीं छोड़ी कोई कसर

राहगीरों और आसपास के लोगों ने बताया पौधरोपण के बाद किसान ने देखभाल पूरी जिम्मेदारी से की है। इसका नतीजा आज है कि पांच साल पहले लगाए गए पौधे अब पेड़ बन गए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए है और भविष्य में और ज्यादा होगी।

वन विभाग ने दिए थे फ्री में पौधे

नरेंद्र लोधी ने बताया दमोह मार्ग पर खेरा गांव में मुख्य मार्ग से लगी उनकी सात एकड़ जमीन है। जहां वह खेती करते हैं। पांच वर्ष पूर्व वन विभाग ने उन्हें नि:शुल्क 600 सागौन के पौधे दिए थे, जो उन्होंने अपने खेत की मेड़ों पर लगा दिए थे। उन्होंने क्षेत्र के लोगों और किसानों को संदेश देते हुए कहा है कि पौधे लगाओ तो उनकी देखरेख करने का काम भी करें। उनकी देखरेख के कारण ही पौधे पेड़ के रूप में लहरा रहे हैं।

अभिनव पहल....साइबर तहसील 2.0 का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया शुभारंभ

प्रदेश में आठ लाख नामांतरण केसों का निपटारा साइबर तहसील से किया जाएगा

न्यायालय बार-बार आने-जाने की आवश्यकता नहीं होने से पैसों और समय की भी बचत होगी

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश सरकार की अभिनव पहल साइबर तहसील 2.0 का शुभारंभ मंत्रालय में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में सुशासन के अंतर्गत संचालित साइबर तहसील 1.0 की सफलता के बाद प्रदेश सरकार की अभिनव पहल है। साइबर तहसील 2.0 में संपदा से प्राप्त अविवादित आंशिक खसरों के क्रय विक्रय आधारित नामांतरण प्रकरणों में क्षेत्रीय तहसील स्तर पर एण्ड टू एण्ड ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से त्वरित निराकरण किया जाएगा। प्रमुख राजस्व आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में प्रतिवर्ष अविवादित नामांतरण के प्रकरणों में औसतन 2 लाख प्रकरण संपूर्ण खसरे के क्रय विक्रय के और 6 लाख प्रकरण आंशिक क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं। साइबर तहसील 1.0 के अंतर्गत अब तक संपूर्ण क्रय विक्रय वाले खसरों का ऑनलाइन नामांतरण तो हो ही रहा था, लेकिन अब साइबर तहसील 2.0 के अंतर्गत आंशिक क्रय विक्रय संबंधी प्रकरणों को भी ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार क्रय विक्रय से संबंधित 8 लाख नामांतरण प्रकरणों का निराकरण अब साइबर तहसील के माध्यम से किया जाएगा।

अब 25 दिन में नामांतरण

साइबर तहसील 2.0 की नवीन व्यवस्था के अंतर्गत प्रकरण दर्ज होते ही पोर्टल द्वारा स्वत: ही ऑनलाइन सूचना पत्र, पटवारी मेमो और प्रथम पेशी दिनांक जारी किए जा सकेंगे। नागरिकों को दावा आपत्ति संबंधी लिंक, आदेश प्रति, अद्यतन खसरा और नक्शों की प्रतियां एसएमएस, व्हाट्सअप या ईमेल के माध्यम से घर बैठे प्राप्त होंगी। पटवारी प्रतिवेदन, खसरा नक्शा ड्राफ्ट संबंधित कार्य ऑनलाइन कर सकेंगे। राजस्व विभाग के इस नवाचार के लागू होते ही पहले जहां नामांतरण प्रक्रिया में औसतन 70 से 100 दिवस लगा करते थे अब वही कार्य 25 दिवसों के भीतर पूर्ण किया जा सकेगा।

समय की भी बचत होगी

राजस्व विभाग के इस के नवाचार साइबर तहसील 2.0 से नागरिकों को भी कम से कम समय में नामांतरण उपरांत आदेश और खसरे एवं नक्शे की अद्यतन प्रति ऑनलाइन ई-मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगी। प्रमुख राजस्व आयुक्त ने बताया कि साइबर तहसील 2.0 की स्वचलित प्रणाली के लागू होने से न केवल शासन के प्रति नागरिकों में विश्वसनीयता बढ़ेगी अपितु क्षेत्रीय तहसील स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यदक्षता में भी वृद्धि होगी। नागरिकों को न्यायालय बार बार आने-जाने की आवश्यकता नहीं होने से पैसों और समय की भी बचत होगी।

घर बैठे मिलेगी सुविधा

अविवादित प्रकरणों का निराकरण, विधिपूर्ण उन्नत तकनीक की सहायता से किया जा सकेगा। साथ ही तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार विवादित प्रकरणों के निराकरण में अधिक समय दे सकेंगे जिससे विवादित प्रकरण भी आपसी सहमति से त्वरित निराकृत होंगे। आधुनिक तकनीक के उपयोग और इस बहुउद्देशीय प्रणाली से नागरिक को एण्ड टू एण्ड रजिस्ट्री से नामान्तरण तक की सुविधा आरसीएमएस पर कम से कम समय में रियल टाइम में ऑनलाइन सिस्टम घर बैठे ही प्राप्त हो सकेगी।

वैज्ञानिकों ने तैयार की बरसीम की दो नई किस्में

चारा खाएंगे पशु और दाने से बनेगी मनुष्यों की सेहत

» दो प्रदेशों में लहलहाएंगी नई किस्में, नोटिफिकेशन जल्द

» सेवन से पाचन तंत्र 70% तक मजबूत होने का दावा

जबलपुर। जागत गांव हमार

शहर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय(जनेकृविवि) में अखिल भारतीय चारा अनुसंधान परियोजना के वैज्ञानिकों ने तेजी से बढ़ते चारे की कमी को पूरा करने के लिए दो नई किस्में तैयार की हैं। इन वैज्ञानिकों ने बरसीम एवं जई की नई प्रजातियां जवाहर बरसीम (जे.बी.08-17) एवं जवाहर ओट (जे.ओ.13-513) तैयार की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने इस शोध में सहयोग किया है। इन किस्मों को 12 राज्यों के लिए चिह्नित किया गया है। जई की प्रजाति जेओ 13-513 का हरे चारे के रूप में पशु प्रयोग कर सकेंगे तो मनुष्य इसके दाने का प्रयोग प्रौष्टिक आहार के रूप में कर सकेंगे। इसमें नौ प्रतिशत प्रोटीन और 14 प्रतिशत फाइबर है। इसके सेवन से पाचन तंत्र 70 प्रतिशत तक मजबूत होने का दावा किया गया है। दूसरी नई फसल जवाहर बरसीम सिर्फ पशुओं के चारे के तौर पर ही उपयोग होगी। यह गीले और सूखे चारे का अच्छा विकल्प है। इसमें 19 प्रतिशत प्रोटीन है।

इन्होंने किया शोध- अखिल भारतीय चारा अनुसंधान परियोजना के तहत इन दो नई फसलों पर विवि के कृषि वैज्ञानिक डॉ. अमित झा, डॉ. पुष्पेंद्र यादव, डॉ.एसके बिलैया, डॉ.एके मेहता, डॉ. आरती श्रीवास्तव, डॉ.एसबी दास ने छह साल तक अनुसंधान किया। उन्होंने पशुओं के लिए लगातार घट रहे चारे की कमी को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया है। फसल की खासियत है कि इससे कम क्षेत्र में भी अधिक उत्पादन मिलता है। जनेकृविवि अभी तक 20 से ज्यादा चारे की किस्म इजाद कर चुका है, जो देशभर में लगाई जा रही हैं। विवि अब इन दोनों फसलों का बीज तैयार कर देशभर के किसानों तक पहुंचाएगा।

इन राज्यों के लिए उपयोगी

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अखिल भारतीय चारा अनुसंधान परियोजना झांसी और बिरसा कृषि विवि रांची में हुई राष्ट्रीय कार्यशाला में इन दोनों फसलों को रखा गया, जहां पर वरिष्ठ विज्ञानियों ने कई चरण पर इन्हें परखने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इसे जारी कर दिया है।

- विवि की अखिल भारतीय चारा परियोजना के वैज्ञानिकों द्वारा जई एवं बरसीम की जो दो प्रजातियां विकसित की हैं। यह प्रदेश एवं देश के पशुपालकों के लिए दुग्ध उत्पादन में सहायक होगी। विवि के वैज्ञानिक पशुपालकों की समस्याओं को नजर में रखते हुए निरंतर चारे की नई किस्में विकसित करने के लिए अग्रसर हैं।

  -प्रो. पीके मिश्रा कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर

- केंद्रीय बीज कमेटी की मोहर लगते ही दोनों नई फसलों के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के अलावा पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, सिक्किम, बिहार और असम के खेतों में इन्हें लगाया जा सकता है।

  डॉ. अमित झा, कृषि वैज्ञानिक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर

राज्यमंत्री ने राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस पर किया आह्वान

अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए स्वदेशी वस्त्र अपनाएं

भोपाल। जागत गांव हमार

कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ग्रामोद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ग्रामोद्योगों से हमारे ग्रामीण बुनकरों, करघाचालकों, दस्तकारों, हस्त शिल्पियों, कारीगरों, कच्चा माल आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों को भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। गांव और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा वोकल फॉर लोकल मंत्र दिया गया है। इसके तहत देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए हम सबको स्वदेशी वस्त्र अपनाना चाहिए। जितना हो सके, खादी के कपड़े पहनिए, यह हर मौसम में शरीर के लिए फायदेमंद है। खादी वस्त्रों की मांग बढ़ने से हमारे बुनकरों और ग्रामीण दस्तकारों को लाभ मिलेगा और वे आर्थिक रूप से सपन्न हो सकेंगे। दरअसल, राज्यमंत्री भोपाल के गौहर महल में दसवें राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस कार्यक्रम और सावन मेले के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।

टिकाऊ कपड़े बनाएं बुनकर

राज्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बुनकरों से आह्वान किया कि वे नए-नए डिजाइन के गुणवत्तापूर्ण टिकाऊ कपड़े बनाकर हमारी देशज संस्कृति को और समृद्ध बनाएं और हम सबको गौरवान्वित होने का अवसर देते रहें। उल्लेखनीय है कि देश के सभी बुनकरों, दस्तकारों और ग्रामीण कारीगरों के हुनर एवं उनके असीम श्रम के सम्मान स्वरूप हर साल अगस्त में राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस समारोह 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में मनाया गया था।

हस्तशिल्पयों को नवाजा

कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री जायसवाल ने मंच से उत्कृष्ट बुनकरों और हस्तशिल्पयों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग विकास बोर्ड मालसिंह, आयुक्त रेशम विकास मदन विभीषण नागरगोजे, मप्र संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के प्रबंध संचालक तथा आयुक्त हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मोहित बुंदस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल के डायरेक्टर आशीष अग्रवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में बुनकर व स्टॉल प्रदर्शक उपस्थित थे।

किसानों को कीटनाशकों से धूम्रपान जितना है कैंसर का खतरा

कृषि में बढ़ता कीटनाशकों का प्रयोग भारत सहित दुनिया भर में किसानों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। एक तरफ फसलों में छिड़का जाने वाला यह जहर कीटों को खत्म करता है, साथ ही इसके संपर्क में आने वाले पौधों, जानवरों और दूसरे जीवों पर भी प्रतिकूल असर डालता है। यहां तक की इसके संपर्क में आने वाले किसानों के स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ता है।

अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कीटनाशकों के संपर्कमें आने से तंत्रिका संबंधी रोगों के साथ-साथ प्रतिरक्षा प्रणाली में गिरावट और यहां तक की कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है।

कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग

कीटनाशकों के स्वास्थ्य पर पड़ते प्रभावों को लेकर अमेरिका में की गई एक नई रिसर्च से पता चला है लम्बे समय तक कुछ कीटनाशकों के संपर्क में रहने से किसानों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अपनी इस रिसचज़् में शोधकर्ताओं ने 69 कीटनाशकों की पहचान की है जो कैंसर के बढ़ते मामलों से जुड़े हैं।

गौरतलब है कि इनमें से कई कीटनाशक ऐसे हैं जिनका भारत में भी धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। इनमें 2,4-डी, एसीफेट, मेटोलाक्लोर और मेथोमाइल जैसे कीटनाशक शामिल हैं, जिनका आमतौर पर भारत में उपयोग फसलों को कीटों और खरपतवार से बचाने के लिए किया जाता है। अमेरिका के रॉकी विस्टा विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकताओज़् के नेतृत्व में किए इस अध्ययन के नतीजे जनज़्ल फ्रंटियर्स इन कैंसर कंट्रोल एंड सोसाइटी में प्रकाशित हुए हैं। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने न केवल सक्रिय रूप से कीटनाशकों का उपयोग करने वाले किसानों बल्कि उन लोगों पर भी बढ़ते प्रभावों को उजागर किया है, जो कीटनाशकों के अत्यधिक संपर्क वाले वातावरण में रहने को मजबूर हैं। अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक कुछ कीटनाशकों के संपर्क में आने से किसानों और आम लोगों में कैंसर का खतरा धूम्रपान जितना ही बढ़ सकता है। इस बारे में अध्ययन से जुड़े वरिष्ठ शोधकर्ता और रॉकी विस्टा विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ ओस्टियोपैथिक मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इसैन जपाटा ने प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से कहा है कि, अध्ययन में सामने आया है कि खेतों में कुछ कीटनाशकों का उपयोग धूम्रपान जितना ही कैंसर कारक हो सकता है।

उनका आगे कहना है कि, जो लोग किसान नहीं हैं, लेकिन खेतों के आसपास रहते हैं, वे वहां इस्तेमाल होने वाले कई कीटनाशकों के संपर्क में आ सकते हैं। यह कीटनाशक उनके पर्यावरण का हिस्सा बन जाते हैं।

स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कीटनाशकों से दूरी: रिसर्च से पता चला है कि कीटनाशकों के संपर्क में आने से नॉन-हॉजकिन लिंफोमा, ल्यूकेमिया और ब्लैडर कैंसर का खतरा धूम्रपान की तुलना में अधिक होता है।

उनका आगे कहना है कि, हमने उन मुख्य कीटनाशकों की सूची बनाई है, जो कुछ कैंसरों के लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि केवल एक ही नहीं, बल्कि उन सभी का संयोजन मायने रखता है।

अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों का उपयोग किया है। इसकी मदद से उन्होंने अमेरिका में 2015 से 2019 के बीच कैंसर की दरों का विश्लेषण किया है।

उन्होंने पाया है कि विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों के अनुसार कैंसर का जोखिम अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी अमेरिका के कुछ हिस्सों में ब्लैडर कैंसर, ल्यूकेमिया और गैर-हॉजकिन लिफोमा की दर विशेष रूप से ऊंची थी।

भारत में भी कीटनाशकों के उपयोग पर ध्यान देना जरूरी है। इसके प्रभावों को नजरअंदाज कर देना सही नहीं है क्योंकि यह सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। किसानों को भी अपनी फसलों में कीटनाशकों का उपयोग करते समय सावधान रहना चाहिए और जितना मुमकिन हो सके उसके उपयोग से बचना चाहिए।

छह फीसदी से भी कम आबादी वाले लोगों के अस्तित्व को खतरा

अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस हर साल नौ अगस्त को मनाया जाता है, यह दिन आदिवासी के अधिकारों को बढ़ावा देने का दिन है। साथ यह दिन उनके भूमि अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं जैसी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी दिन है। आज के दिन आदिवासी इतिहास और परंपराओं पर शैक्षिक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, दुनिया भर में लगभग 200 आदिवासी या स्वदेशी लोग रहते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस

आदिवासी, बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, पेरू और वेनेजुएला के सुदूर जंगलों में रहते हैं, तथा अपनी संस्कृतियों और भाषाओं को संरक्षित रखने के लिए भोजन इकट्ठा करने और शिकार पर निर्भर हैं।

आदिवासी या स्वदेशी लोग लंबे समय से अपनी पहचान, जीवन शैली और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों की मांग करते आए हैं। उनके प्रयासों के बावजूद, पूरे इतिहास में उनके अधिकारों का लगातार उल्लंघन किया गया है।

उनके प्राकृतिक आवास में होने वाले बदलावों के कारण उनके अस्तित्व को खतरा है, इसलिए दुनिया भर में स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के प्रयास में, संयुक्त राष्ट्र हर साल विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है।

यह दिन आदिवासियों की अनूठी संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं को मान्यता देता है, साथ ही दुनिया भर में विविधता और सतत विकास में उनके योगदान का भी उल्लेख करता है। साथ ही भेदभाव, हाशिए पर डाले जाने और अपनी पैतृक भूमि खोने जैसी चुनौतियों को भी सामने लाता है।

इसके अलावा यह दिन सरकारों, संगठनों और लोगों को स्वदेशी लोगों के अधिकारों को बनाए रखने, उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और न्याय, समानता और सामंजस्य हासिल करने की दिशा में काम करने के लिए कार्रवाई करने का आह्वान करता है।

आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र में शामिल किए गए अधिकारों के बावजूद भी आदिवासियों को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें अक्सर आसपास की दुनिया द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। उनके रहने वाले इलाकों में खेती, खनन, पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों के विकास के कारण आदिवासियों के जंगलों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो रहा है, जिससे उनकी जीवन शैली पर बुरा असर पड़ रहा है और प्राकृतिक पर्यावरण नष्ट हो रहा है जिसे उन्होंने पीढ़ियों से संरक्षित किया था।

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में आदिवासी आबादी की बात करें तो यहां लगभग 10 करोड़ 40 लाख आदिवासी रहते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या के लगभग 8.6 फीसदी के बराबर है। भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा में सबसे ज्यादा जनजाति आदिवासी रहते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की मानें तो आदिवासी लोगों की संख्या दुनिया भर की जनसंख्या का छह फीसदी से भी कम है, इनमें 15 फीसदी भारी गरीबी में जी रहे हैं।

आदिवासी या स्वदेशी लोग धरती के 28 फीसदी हिस्सों में रहते हैं और दुनिया के 11 फीसदी जंगल उनके रहने के इलाकों में शामिल हैं। वे दुनिया की अधिकांश बची हुई जैव विविधता के संरक्षक हैं।

आदिवासी या स्वदेशी लोगों की खाद्य प्रणालियों में आत्मनिर्भरता का स्तर सबसे अधिक है, जो भोजन और संसाधनों के उत्पादन में 50 से 80 फीसदी तक है।

आदिवासी दुनिया की लगभग 7,000 भाषाओं में से अधिकांश बोलते हैं और 5,000 अलग-अलग संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ग्रामीण युवाओं के लिए बढ़ते शैक्षिक अवसरों के साथ जागरूकता जरूरी

» दीप्ति दुबे, प्रवक्ता (इतिहास)
सर्वोदय कन्या विद्यालय
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली

दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका होने के नाते, मुझे विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षित करने का सौभाग्य मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में कई सालों का अनुभव होने के बाद, मैंने देखा है कि कैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के बीच अवसरों और जागरूकता का अंतर होता है। विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के लिए, शैक्षिक अवसरों के बढ़ते दायरे के साथ सही जागरूकता की अनिवार्यता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक संस्थानों का विस्तार और गुणवत्ता में वृद्धि की गई है। स्कूलों में बुनियादी ढाँचे का विकास, डिजिटल शिक्षा का प्रचलन, और शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकों का समावेश हुआ है। फिर भी, इन अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए सही जागरूकता का होना आवश्यक है।

इस संदर्भ में, मैं एक वास्तविक जीवन की कहानी साझा करना चाहूँगी जो इस मुद्दे को उजागर करती है। यह कहानी है सविता की, जो दिल्ली के पास स्थित एक छोटे से गाँव की रहने वाली है। सविता के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके माता-पिता ने उसकी शिक्षा पर हमेशा ध्यान दिया। सविता का सपना था कि वह एक दिन एक सफल डॉक्टर बने और अपने गाँव के लोगों की मदद करे।

सविता के गाँव में एक सरकारी स्कूल था, लेकिन वहाँ के शिक्षक और सुविधाएँ सीमित थीं। फिर भी, सविता ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और अपने स्कूल में हमेशा अव्वल आई। जब वह दसवीं कक्षा में पहुँची, तो उसे अपने आगे की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। उसके स्कूल के एक शिक्षक ने उसे दिल्ली के एक अच्छे सरकारी स्कूल में दाखिला लेने की सलाह दी, जहाँ अधिक अवसर और बेहतर संसाधन उपलब्ध थे। सविता के माता-पिता ने उसे दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। दिल्ली आकर सविता को एक नए माहौल में ढलने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन उसने अपनी मेहनत और समर्पण से सभी चुनौतियों का सामना किया। उसने दिल्ली के स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखी और हर परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए। दिल्ली के स्कूल में सविता को नए-नए शैक्षिक अवसर मिले। उसे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिला, और उसने विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि सविता को इन सभी अवसरों का लाभ इसलिए मिल पाया, क्योंकि उसे सही समय पर सही जागरूकता मिली। शिक्षक और माता-पिता ने उसे सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। ग्रामीण युवाओं के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है सही जागरूकता। जागरूकता के अभाव में वे इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते और उनकी प्रतिभा और क्षमता अनदेखी रह जाती है। जागरूकता के माध्यम से ही ग्रामीण युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता

शिक्षा के महत्व का प्रचार-प्रसार: ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। गाँवो में जनसभाओं, कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है।

शिक्षकों की भूमिका: ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्हें बच्चों को शिक्षा के महत्व और शैक्षिक अवसरों के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए। साथ ही, उन्हें बच्चों के माता-पिता को भी जागरूक करना चाहिए।

सरकारी योजनाओं की जानकारी: सरकारी शिक्षा संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इसके लिए पंचायतों, स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है।

करियर काउंसलिंग: ग्रामीण युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वे अपने करियर के लिए सही दिशा चुन सकें। इसके लिए स्कूलों में करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।

प्रेरणा दायक कहानियों का प्रचार: ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों की कहानियों का प्रचार किया जाना चाहिए जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद शिक्षा के माध्यम से सफलता हासिल की है। इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और वे गंभीर होंगे।

सविता की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे सही जागरूकता और सही मार्गदर्शन से किसी के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। ग्रामीण युवाओं के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही सही जागरूकता भी अनिवार्य है। हमें इस दिशा में काम करना होगा, ताकि हर बच्चे को अपने सपनों को साकार करने का मौका मिल सके।

दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक होने के नाते, मैं अपने अनुभव से यह कह सकती हूँ कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यदि हम सही दिशा में प्रयास करें और ग्रामीण युवाओं को सही मार्गदर्शन और जागरूकता प्रदान करें, तो हम न केवल उनके जीवन में बल्कि पूरे समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकतेहैं।

मुझे विश्वास है कि यदि हम सभी मिलकर इस दिशा में काम करें, तो वह दिन दूर नहीं जब हर ग्रामीण बच्चा अपने सपनों को साकार कर सकेगा और हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल होगा।

ग्रामीण भारत में चिंताओं से जूझ रहे 45 फीसदी लोग, 73 फीसदी बुजुर्गों को देखभाल की जरूरत

दिल्ली की ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) ने स्टेट ऑफ हेल्थकेयर इन रूरल इंडिया- 2024 रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुजुर्ग सदस्यों वाले ग्रामीण भारतीय परिवारों में से 73 फीसदी ऐसे हैं जिन्हें निरंतर देखभाल की जरूरत पड़ती है, जिसकी अधिकतर जिम्मेवारी महिलाओं पर होती है। भारी मांग के बावजूद केवल तीन फीसदी परिवार ही पैसे देकर देखभाल सेवाओं का विकल्प चुन पाते हैं, जो स्वास्थ्य के देखभाल में एक बड़े अंतर को सामने लाता है।

रिपोर्टज़् में कहा गया है कि 21 राज्यों के 5,389 से अधिक परिवारों को शामिल करने वाले इस विस्तृत सर्वेक्षण से अनौपचारिक तौर पर पारिवारिक देखभाल करने वालों पर भारी निभज़्रता का पता चलता है, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं हैं, जिनका देखभाल करने वालों में 72.1 फीसदी हिस्सा है।

रिपोर्ट में पारिस्थितिकी, सामाजिक-महामारी विज्ञान के नजरिए से सामने लाए गए इस मॉडल का उद्देश्य केवल तकनीकी समाधानों पर निर्भर रहने के बजाय स्वास्थ्य को व्यापक रूप से देखा गया है। स्थानीय स्वास्थ्य समितियों, स्वयं सहायता समूहों और समुदाय के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करना पड़ोस की देखभाल को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

रिपोर्ट में नेबहुड ऑफकेयर की अवधारणा को शामिल किया गया है, जो स्वास्थ्य सेवा के लिए एक परिवतज़्नकारी, समुदाय-केंद्रित नजरिए की बात करता है जो इन चुनौतियों का समाधान करता है। यह मॉडल पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों से हटकर एक ऐसी प्रणाली की ओर बदलाव का सुझाव देता है जो सामाजिक और पारिस्थितिक कारणों को शामिल करती है, स्वास्थ्य पेशेवरों, सामुदायिक संगठनों और निवासियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है।

ग्रामीण इलाकों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं (एंग्जायटी) भी बढ़ रही हैं, जहां सभी लिंगों के 45 फीसदी उत्तरदाताओं ने चिंता संबंधी समस्याओं की बात कही गई है, जिससे व्यापक सहायता प्रणालियों की आवश्यकता का पता चलता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य सिर्फ सुविधाओं से कहीं अधिक है, यह लोगों और परिवारों को उनके रोजमर्रा के जीवन में सहायता करने के बारे में है। चिंता के उच्च स्तर और बुजुर्गों की देखभाल की बढ़ती जरूरतों के साथ, हमें देखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण और सहायता को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो मुख्य रूप से महिलाएं हैं।

-किसान बचाव में अपनाएं मैकेनिकल तरीका

सावधान! सोयाबीन पर बढ़ा सफेद मक्खी का खतरा

भोपाल। जागत गांव हमार

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से सोयाबीन की फसलों पर सफेद मक्खी और रस चूसक कीटों का प्रभाव बढ़ गया है। समस्या से निपटने के लिए किसान सीधे तौर पर फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। फसलों पर इसके प्रभाव को कम करने और कम खर्च में इसके निपटान के लिए किसानों को मैकेनिकल तरीका अपनाना चाहिए, ताकि फसलों पर कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग को कम किया जा सके। रिमझिम बारिश के साथ तापमान में उतार-चढ़ाव के चलते फसलों में कीटों और इल्लियों के लिए मौसम अनुकूल हो गया है। जिसके कारण यह तेजी से पनप रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्तमान में सोयाबीन और सब्जियों की फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान निराई-गुड़ाई जल्द शुरू करें। साथ ही सभी फसलों में सफेद मक्खी और रस चूसक कीटों की नियमित निगरानी करें। साथ ही बैज्ञानिकों ने बताया कि सोयाबीन की फसल में पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार की बर्ड पर्चेस लगाएं। इससे कीटभक्षी पक्षियों द्वारा कीटों, मक्खी और इल्लियों की संख्या कम करने में सहायता मिलेगी।

इस विधि से बचाएं फसल

मैकेनिकल विधि में किसान को टी आकार की खूंटियां खेत में फसल के बीच लगानह चाहिए। किसान प्रति हेक्टेयर में 35 से 40 खुटियां लगा सकते हैं। खेतों में लगी खूटियों पर पक्षी आकर बैठेंगे और इल्लियों को खाकर फसल को निर्यत्रित करेंगे। किसानों को इस बात का भी ध्यान रहे कि खेत में लगी खुटियां फली में दाना भरते समय निकाल लें।

उर्वरकों का खर्च बढ़ा

खेती में साल-दर-साल रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का खेती में उपयोग बढ़ते जा रहा है। ऐसे में एक वर्ष के दौरान किसान रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर अधिक खर्च कर रहे हैं। इस लिहाज से दोनों सीजन में किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 10 हजार रुपये के रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों खर्च कर रहे हैं। ऐसे में रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग में कमी लाने के लिए किसानों को विभागीय स्तर पर जागरूक किया जा रहा है। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते फसलों पर कीट, मक्खी और इल्लियों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। जिनके नियंत्रण के लिए किसानों को सलाह दी जा रही है।

केंद्र सरकार ने संसद में पेश किया आंकड़ा

दाल-सब्जी के मुकाबले बढ़ रही अंडे-मछली और मीट की डिमांड

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में सब्जी-अनाज की डिमांड घट रही है। जबकि अंडे-मछली और मीट की डिमांड में इजाफा हो रहा है। ये कहना है केन्द्र सरकार का। संसद में उठे एक सवाल के जवाब में खुद सरकार ने इससे संबंधित आंकड़े भी पेश किए हैं। सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है और पशुपालन से जुड़े प्रोडक्ट का योगदान बढ़ रहा है। गौरतलब रहे देश में लगातार अंडे-मछली और मीट का उत्पादन बढ़ रहा है। एक्सपर्ट की मानें तो पोल्ट्री सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर बन गया है। वहीं मीट उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। जबकि मछली का उत्पादन करीब 174 लाख टन पर पहुंच गया है। कोरोना के बाद से इसमे और तेजी देखी जा रही है। हाल ही में लोकसभा में एक सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी ने पशुधन उत्पाद की डिमांड का मामला उठाया था। इसी के संबंध में सरकार ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आंकड़े पेश किए हैं। केन्द्र सरकार ने लोकसभा में अंडे-मछली और मीट की डिमांड बढ़ने के जो आंकड़े सामने रखे हैं उसके मुताबिक साल

2011-12 के मुकाबले साल 2021-22 में मछली की डिमांड 33 फीसद बढ़ी है। जबकि अंडे की डिमांड में 47 फीसद का इजाफा हुआ है। वहीं सभी तरह के मीट की बात करें तो उसकी डिमांड 31 फीसद बढ़ी है। इस आंकड़े को सरकार ने अनुमान के तौर पर बताया है। गौरतलब रहे भारत बफैलो मीट एक्सपोर्ट के मामले में टॉप पर है। जबकि पोल्ट्री सेक्टर की बात करें तो विश्व अंडा उत्पादन में भारत तीसरे तो चिकन उत्पादन के मामले में आठवें स्थान पर है। बीते साल ही देश में 14 हजार करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ था। जबकि मीट की बात करें तो करीब एक करोड़ टन मीट का उत्पादन हुआ था। इसमे चिकन की हिस्सेदारी करीब 50 लाख टन थी। वहीं मछली का उत्पादन 174 लाख टन पर पहुंच गया है। वहीं झींगा भी 10 लाख टन को पार कर चुका है।

एक साल में बढ़ गया 25 करोड़ मुर्गो का प्रोडक्शन

ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म में चिकन के लिए मुर्गों को तैयार किया जाता है। पशुपालन मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि बीते साल के मुकाबले 25 करोड़ मुर्गों को प्रोडक्शन बढ़ गया है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021-22 में 306 करोड़ मुर्गों का चिकन खाया गया था। इस चिकन की मात्रा 48 लाख टन थी। जबकि साल 2022-23 में 331 करोड़ मुर्गों का 50 लाख टन चिकन खाया गया है। चिकन का प्रोडक्शन बढ़ने के पीछे पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रनपाल डाहंडा ने बताया कि सभी तरह के मीट में चिकन सबसे सस्ता आइटम है। इसमे किसी दूसरे मीट की मिलावट भी नहीं हो सकती है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि चिकन में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है।

-पंच,सरपंच और जनपद सदस्य के लिए होगी वोटिंग

पंचायत और निकाय उप-चुनाव की तारीख घोषित

भोपाल। जागत गांव हमार

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। उप निर्वाचन के लिए मतदान 11 सितंबर 2024 को होगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अभिषेक सिंह ने जानकारी दी है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य 21 अगस्त से शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र 28 अगस्त तक लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 29 अगस्त को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख 31 अगस्त है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी किया जाएगा। त्रि-स्तरीय पंचायतों में मतदान सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा।

15 को आएगा परिणाम

पंच पद के लिए मतगणना, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के लिये ईवीएम से की जाने वाली मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर 15 सितंबर को सुबह 8 बजे से होगी। परिणाम भी 15 सितंबर को ही घोषित किए जाएंगे। नगरीय निकायों में मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा 13 सितंबर को सुबह 9 बजे से होगी। उप निर्वाचन में 5344 पंच, 34 सरपंच और 4 जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतदान होगा। इसी तरह नगरीय निकायों में 13 पार्षदों के लिए मतदान होगा।

बांग्लादेश में संकट के कारण प्याज के निर्यात पर असर, प्याज के दाम 2800-3000 रुपए प्रति क्विंटल

टमाटर-प्याज और आलू के भाव में गिरावट, अब नरम पड़ी लहसुन

भोपाल। जागत गांव हमार

बांग्लादेश में उपजे संकट का असर प्याज के निर्यात पर पड़ सकता है। अभी तो ज्यादा असर नहीं दिख रहा, लेकिन सीमाएं बंद रही और वहां स्थिति खराब बनी रही तो भारत से जाने वाली प्याज की खेप अटकने से कारोबारियों को आगे नुकसान होगा। इस बीच मध्यप्रदेश के इंदौर की देवी अहिल्या बाई होलकर थोक मंडी में प्याज की आवक 40 हजार बोरी हो रही है। प्याज के भाव स्थिर हैं। बेस्ट माल ऊपर में 2800-3000 रुपए तक बिका। अच्छी क्वालिटी में गोल्टा प्याज भी 2700 रुपए तक बिक रहा है। आलू के भाव में अभी स्थिरता है। एक-दो लाट ही ऊपर में 2400 रुपए बिके। आलू की आवक करीब 5-6 हजार बोरी रही। कारोबारियों को राखी के लेवाली का इंतजार है। टमाटर के दाम में गिरावट आई है। टमाटर औसतन 1200 रुपए के आस-पास बिका। टमाटर मंडी में अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। कहा जा रहा है कि अभी और दाम गिरेंगे। वहीं लहसुन की आवक 7 हजार बोरी की हो रही है, लेकिन दाम बीते सप्ताह के मुकाबले नरम ही है। लहसुन ऊपर में एक-दो लाट बेस्ट क्वालिटी होने पर 2000 रुपए तक बिकती है। शेष माल बेस्ट में ऊपर में 17000-19000 रुपए क्विंटल तक बिक रही है।

टमाटर

औसत मूल्य- 1225 रुपए क्विंटल
न्यूनतम मंडी मूल्य-200रु. क्विंटल
उच्चतम मंडी मूल्य-2000रु.क्विंटल

प्याज

बेस्ट- 2800 से 3000 रुपए क्विंटल
एवरेज और गोल्टा- 2500-2800
गोल्टी- 1800 से 2000रु. क्विंटल

आलू

चिप्स बेस्ट- 2200 से 2400 रु. क्विंटल
ज्योति- 2000 से 2100 रुपए क्विंटल
आगरा- 1300 से 1500 रुपए क्विंटल
एवरेज- 1100-1200 रुपए क्विंटल
गुल्ला- 700-900 रुपए प्रति क्विंटल

लहसुन

ऊंटी 18000 से 19000 रु. क्विंटल
बोल्ड 15000 से 17000रु. क्विंटल
मीडियम 12000-14000रु.क्विंटल
बारीक 8000-10000 रु. क्विंटल
मेथी- 5700 रुपए क्विंटल
अलसी- 4899 रुपए क्विंटल
सोयाबीन -3101 से 4423 रु. क्विंटल
मटर- 4400 से 7375 रुपए क्विंटल

कान्हा परिदृश्य में कोदो-कुटकी नेटवर्क फॉर कंवर्जिंग सेंट्रल इंडिया का तीसरा कृषि जैवविविधता राउंडटेबल सम्मेलन

कोदो और कुटकी को बढ़ावा देने मंडला में हुआ राउंडटेबल सम्मेलन

सय्यैद जावेद अली। मंडला

कान्हा परिदृश्य भारत के कुछ शेष स्थानों में से एक है, जहां अभी भी कोदो और कुटकी उगाए जाते हैं। 6 और 7 अगस्त को नेटवर्क फार कन्वर्जिंग सेंट्रल इंडिया द्वारा आयोजित एक राउंडटेबल सम्मेलन मंडला में आयोजित किया गया, जो कि कोदो-कुटकी का देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। जिसने कई नागरिक समाज संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए ज्ञान का आदान-प्रदान करने और कान्हा क्षेत्र में कोदो-कुटकी की खेती और व्यवसायीकरण के प्रयासों को एकजुट करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।

अगस्त 2023 और जनवरी 2024 में पिछले राउंडटेबल सम्मेलनों पर निर्माण करते हुए इस कार्यक्रम ने कृषि जैवविविधता बनाए रखने, कोदो-कुटकी के स्थानीय उपभोग को प्रोत्साहित करने, और वैज्ञानिक विशेषज्ञता और पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को संलयन करने के महत्व पर जोर दिया। प्रतिभागियों ने सतत कोदो-कुटकी की खेती प्रथाओं, खाद्य सुरक्षा और पोषण, और कोदो-कुटकी की प्रसंस्करण और विपणन में सुधार की रणनीतियों पर चर्चा की। रिलायंस फाउंडेशन, समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रदान, अर्थ फोकस, वासन, कीस्टोन फाउंडेशन, नर्मदा किसान उत्पादक संगठन लिमिटेड, मंडला, फाउंडेशन, पारसटोला स्वयं सहायता समूह, गांधी ग्राम विकास समिति इंडिया, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी फाउंडेशन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया सहित संगठनों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया। नर्मदा एफपीओ के सदस्य बिरजो बाई ने साझा किया, हमें मिलेट्स पर काम कर रहे अन्य लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनके साथ जुड़ने का मौका मिलता है।

समूह ने नर्मदा सेल्फ रिलायंट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, कुटेली में एक साइट विजिट और स्थानीय एफपीओ सदस्यों और निदेशक मंडल के साथ चर्चा (बैठक) भी की। परसटोला एसएचजी की निदेशक ज्योति मोगरे ने प्रतिबिंबित किया। बहुत से लोग विभिन्न संगठनों और पृष्ठभूमियों से आए थे, इसलिए उनके दृष्टिकोण को सुनना मददगार था। कुटेली में रिलायंस फाउंडेशन के एफपीओ के साइट विजिट से विशेष रूप से मदद मिली क्योंकि हम वहां से विचार लेकर अपने एफपीओ में लागू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, मंडला की कृषि उपनिदेशक मधु अली ने कोदो-कुटकी की उत्पादकता बढ़ाने, एफपीओ की प्रसंस्करण शक्ति में सुधार करने, और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया। राउंडटेबल सम्मेलन के बारे में उसने कहा, राउंडटेबल एनसीसीआई की एक अनूठी पहल है जिसमे मिलेट्स एंड एग्री बायोडायवर्सिटी को लेकर सभी संस्थाओं के द्वारा रखे गए विचार विमर्श बहुत ही सार्थक है इस तरह के आयोजन नियमित होते रहना चाहिए।

संस्थाएं कोदो-कुटकी के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए काम कर रहीं

राउंडटेबल सम्मेलन ने बीज या संरक्षक किसानों के लिए संरचनात्मक समर्थन बनाने, मिलेट्स के लिए लैंडस्केप ब्रांड बनाने और गुणवत्ता उत्पाद सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसके अतिरिक्त, राउंडटेबल सम्मेलन ने उपभोक्ताओं को कोदो-कुटकी के पोषण और पारिस्थितिक लाभों के बारे में शिक्षित करने के महत्व को रेखांकित किया ताकि स्थानीय उपभोग और बाजार की मांग बढ़ाई जा सके।

एनसीसीआई की संस्थापक-निदेशक, प्रोफेसर रूथ डिफ्रीज (कोलंबिया विश्वविद्यालय) ने कहा, कोदो-कुटकी न केवल सूखा-रोधी और पोषक होते हैं, बल्कि वे इस क्षेत्र की जैविक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। यह दिल को सुकून देता है कि इतनी सारी संस्थाएं कोदो-कुटकी के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। समूह जनवरी 2025 में फिर से एकत्रित होगा, ताकि कार्य अद्यतन और अनुसंधान निष्कर्षों का आदान-प्रदान किया जा सके और कान्हा परिदृश्य में कोदो-कुटकी के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा दिया जा सके।

नेटवर्क फार कंवर्जिंग सेंट्रल इंडिया के बारे में: नेटवर्क फार कंवर्जिंग सेंट्रल इंडिया एक नेटवर्क है, जो केंद्रीय भारतीय परिदृश्य में लोगों और प्रकृति की 'जुगलबंदी' बनाए रखने के लिए ज्ञान को कार्रवाई से जोड़ने के लिए समर्पित है।

मूंगफली, उड़द और सोयाबीन फसल के प्रमुख कीटों पर किसानों को प्रशिक्षण

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार के निर्देशन में केंद्र के वैज्ञानिकों डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके जाटव एवं जयपाल छिगारहा द्वारा विगत दिवस ग्राम कोडिया में प्रमुख खरीफ फसलों के कीटों के प्रबंधन पर कृषक प्रशिक्षण एवं फसलों का भ्रमण किया। कृषक प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों को मूंगफली, उड़द एवं सोयाबीन फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों के प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया।

मूंगफली फसल के प्रमुख कीट- सफेद लट, बिहार रोयेदार इल्ली, माहूए दीमक, सफेद मक्खी एवं थ्रिप्स आदि मूंगफली फसल की पत्तियां खाकर या रस चूसकर फसल को हानि पहुंचाते हैं। पत्तियों को खाने और रस चूसने वाले कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए मिश्रित कीटनाशक दवा एसिटामिप्रिड, बायफेन्थ्रिन 25: डब्लूजी 100 ग्रा. प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। सफेद लट और दीमक की समस्या वाले खेतों में बोवनी के समय कार्बोफ्युरान 3 जी 10 किग्रा./एकड़ का प्रयोग करना चाहिए। बिहार रोयेदार इल्ली के लिए दवा इंडोक्साकार्ब 15.8: ईसी 125 मिली. या लैम्ब्डा साइहलोथ्रिन 9.5: जेडसी 120 मिली./एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए।

उड़द फसल के प्रमुख कीट- फली बीटल कीट का प्रकोप अधिक होता है। इस कीट की इल्लियां बीज पर तथा छोटे पौधों की पत्तियों में छेद करती हैं, जिससे पत्तियों पर छेद ही छेद दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार पत्ती भेदक इल्लियां भी पत्तियों को खाकर पौधों को हानि पहुंचाती हैं। इसके अलावा चूसक कीटों में सफेद मक्खी, काली माहू, जैसिड एवं फुदकाए इस प्रकार के कीटों के साथ नियंत्रण हेतु पूर्व मिश्रित दवाएं जैसे क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 9.30: . लैम्ब्डा साइहलोथ्रिन 9.50: जेडसी या थियामेथोक्सम 12.60: . लैम्ब्डा साइहलोथ्रिन 9.50: जेडसी 60 मिली या बीटा.साइफ्लुथ्रिन . इमिडाक्लोप्रिड 150 मिली की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

सोयाबीन फसल के प्रमुख कीट

चने की इल्ली, बिहार रोयेदार इल्ली, चक्रभृंग, तना मक्खीए, सेमीलूपर इल्ली, तम्बाकू की इल्ली आदि पत्तियों को खाकर या रस चूसकर फसल को हानि पहुंचाते हैं। पत्ती खाने वाली सेमीलूपर, तम्बाकू इल्ली, चने की इल्ली, बिहार रोयेदार इल्लियों के नियंत्रण हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9: ईसी 170 मिली./एकड़ या फ्लूबेंडियामाइड 39.35: एससी 60 मिली./कड़ या नोवलुरॉन 5.25:. इंडोक्साकार्ब 4.5: एससी 350 मिली./एकड़ और रस चूसक कीटों से बचाव हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8: एसएल 80.100 मिली/एकड़ या एसिटामिप्रिड 25:. बायफेन्थ्रिन 25: डब्ल्यूजी;100 ग्रा/एकड़ दवा का छिड़काव करें। यदि फसल में पत्ती खाने वाले और रस चूसने वाले कीट एक साथ दिख रहे हैं तो उस स्थिति में थियामेथोक्सम 12.6:. लैम्ब्डा साइहलोथ्रिन 9.5: जेडसी 60 मिली/एकड़ या बीटा.साइफ्लुथ्रिन. इमिडाक्लोप्रिड ;140 मिली/एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। पौधों में पीला मौजेक या सोयाबीन मौजेक रोग के लक्षण दिखने पर ऊपर दर्शायी गयी दोनों दवाओं में से किसी एक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। फसल में एन्थ्रेक्नोज रोग के लक्षण दिखने पर टेबुकोनाजोल 25.9: ईसी 250 मिली/एकड़ या कार्बेन्डाजिम 12:. मैनकोजेब 63: डब्ल्यूपी 500 ग्रा./एकड़ और राइज़ोक्टोनिया एरियल ब्लाइट रोग से बचाव हेतु फफूंदनाशक दवा पाइराक्लोस्ट्रोबिन 20: डब्ल्यूएजीए ;150.200 ग्रा./एकड़ का छिड़काव करना चाहिए।

पशु चिकित्सा अधिकारियों का उन्नत पशुपोषण तकनीकियों पर प्रशिक्षण

दतिया। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र दतिया में उन्नत पशुपोषण तकनीकियां विषय पर एक दिवसीय पशुचिकित्सा अधिकारियों का अंत: सेवाकालीन प्रशिक्षण गत दिवस केन्द्र प्रमुख डॉ. अवधेश सिंह के मार्गदर्शन एवं विषय विषेशज्ञ डॉ. रूपेश जैन के तकनीकी निर्देशन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में पशुपालन विभाग के 25 पशुचिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के उद्घाटन अवसर पर उपसंचालक पशुचिकित्सा डॉ. दास द्वारा पशुपालकों को पशुओं के लिये संतुलित आहार हेतु प्रेरित करने की सलाह दी गई।

केन्द्र प्रमुख डॉ. अवधेश सिंह ने संतुलित संपूरक आहार मिनरल सप्लीमेंट एवं नमक की पशु आहार में उपयोगिता एवं उसके पशुपालन पर पड़ने वाले प्रभाव को वैज्ञानिक तरीके से बताया। तकनीकी सत्र में प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. रूपेश जैन द्वारा दुधारू पशुओं के लिये संतुलित आहार तैयार करने की विधि के साथ-साथ दुधारू पशुओं को वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए एक आदर्श पशु चारा उत्पादन फसल चक्र को समझाया गया। उन्होंने बताया कि पशुओं को साल भर हरे चारे के साथ-साथ हरे चारे को संरक्षित करने के लिये साइलेज बनाना एक बहुत उपयोगी तकनीकी है। इस तकनीकी की मदद से किसान हरे चारे को साइलेज में परिवर्तित कर सकते हैं जिसको किसान उस समय पशुओं को खिला सकते हैं जबकि सामान्यत: हरा चारा खेतों में उपलब्ध नहीं रहता इससे पशुओं का दुग्ध उत्पादन भी संतुलित रहता है। हरे चारे की पूर्ति भी साइलेज के रूप में होती रहती है। इसके साथ-साथ डॉ. जैन ने यूरिया मोलिसिस मिनरल ब्लॉक, कम्पलीट फीड ब्लॉक और सूखे चारे को यूरिया से उपचारित करने की विधि को भी विस्तार पूर्वक बताया साथ ही उन्होंने दुधारू पशुओं के लिए अजोला उत्पादन तकनीकी एवं हाइड्रोपॉनिक हरा चारा उत्पादन तकनीकी को भी अधिकारियों को विस्तार से बताया। कार्यक्रम में पशुचिकित्सा विभाग के डॉ. महेन्द्र परिहार, डॉ. शिवा गुप्ता सहित लगभग 25 पशुचिकित्सा अधिकारी एवं गौसेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आभार केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. व्हीएस कंसाना द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्र की बकरीपालन, मुर्गीपालन, वर्मीकम्पोस्ट, अजोला, हरा चारा आदि इकाइयों का भ्रमण कराया गया।

सफेद चंदन की खेती मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में

किसान सात हजार पौधे करते हैं तैयार

चंबल में चंदन की खेती से 15 लाख रु. की कमाई, फूल-पत्ती, टहनियां सब बिकती हैं

श्योपुर। जागत गांव हमार

चंबल अब चंदन की खुशबू से महक रहा है। श्योपुर के एक किसान ने पारंपरिक खेती छोड़ चंदन की खेती के साथ नर्सरी शुरू की है। 7 साल पहले दो बीघा में 200 पौधे लगाए थे, जो अब पेड़ बन गए हैं। इनकी फूल, पत्ती, टहनियों और नर्सरी से हर साल लगभग 15 लाख की कमाई कर रहा है। 6-7 साल बाद यही पेड़ 4 करोड़ से ज्यादा में बिकेंगे। वह दूसरे किसानों को भी चंदन की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। **जागत गांव हमार** अपने इस अंक में श्योपुर जिले के बगदरी गांव के रहने वाले किसान कर्म सिंह से मिलवा रहा है। कर्म सिंह दो बीघा जमीन में 200 चंदन के पौधे लगाए हैं। पौधों के बीच दूसरी फसलों की भी खेती कर रहे हैं। इसके अलावा आधे बीघा में चंदन की नर्सरी लगाए हैं। जहां से हर साल करीब 6 से 7 हजार से ज्यादा चंदन के पौधे सप्लाई हो जाते हैं। एक पौधा 200 रुपए में बेचते हैं।

आइए कर्म सिंह से ही जानते हैं कि कैसे शुरू की खेती- 2010 के पहले मैं भी दूसरे किसानों की तरह ही धान, गेहूं, सरसों और मूंग की खेती करता था, जिससे सिर्फ घर खर्च ही चल पाते थे। फिर कृषि विभाग के सहयोग से मुझे भारत भ्रमण करने का मौका मिला। इस दौरान मैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों में गया। वहां कई खेती की किस्मों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक के बारे में भी जाना। फिर मैंने सोचा कि अपने श्योपुर सहित चंबल में क्या-क्या कर सकते हैं, जिससे किसानों को मोटा मुनाफा हो। साथ ही पर्यावरण के लिए भी फायदा हो। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा चंदन की खेती पर फोकस ज्यादा रहा। मैं कश्मीर में तीन दिन रुका। वहां से केसर भी लाया था, लेकिन केसर के लिए जो वातावरण चाहिए वो यहां नहीं है। चंदन की खेती के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं दो बीघा में 10-10 फीट की दूरी पर खेत के चारों ओर और अंदर 200 चंदन के पौधे लगाए। जो अब 6 से 7 साल के हो गए हैं। इन पौधों से फूल और फल आने शुरू हो गए हैं। बाजार में फूल एक से डेढ़ हजार रुपए किलो में बिकते हैं। 6 साल के एक पेड़ में एक से डेढ़ किलो तक फूल निकलते हैं। फिर जैसे-जैसे पेड़ बड़े होते हैं। वैसे-वैसे फल और फूल बढ़ने लगते हैं। इसकी मार्केट में डिमांड भी रहती है। क्योंकि भारत में चंदन के फूल से कई महत्वपूर्ण औषधियां बनाई जाती हैं। चंदन के बीज का महिलाओं के मेकअप में इस्तेमाल किया जाता है।

भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कर सकते हैं खेती

सफेद चंदन की खेती के लिए कोई खास कानूनी प्रा या नहीं है। भारत सरकार ने 2021 में इस पर गाइडलाइन बनाई है। इस गाइडलाइन के अनुसार कोई भी चंदन की खेती कर सकता है। कुछ साल पहले तक चंदन की खेती प्रतिबंधित थी, यानी सरकार की अनुमति लेकर ही किसान चंदन की खेती किया करते थे।

चंदन के पत्तों से लेकर जड़ तक कीमती

चंदन के पेड़ की पत्ती, टहनी से लेकर जड़ तक बहुत कीमती है। बाजार में चंदन की पत्ती और टहनियां 200 रुपए किलो बिकता है। जड़ तीन हजार रुपए किलो बिकती है। पेड़ के अंदर से निकलने वाला ऑयल भी बहुत महंगा मिलता है। इटली में इसकी शराब बनती है। एक बोतल की कीमत लगभग 11 लाख रुपए होती है। चंदन के पेड़ में निकलने वाली लाल रंग की रोड़ देश में 8 से 10 हजार रुपए किलो में बिकता है। चंदन के पेड़ का एक-एक पत्ता तक मार्केट में बिक जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पारंपरिक फसलों की तुलना में चंदन की खेती कितने फायदेमंद है।

लाल और सफेद दो प्रकार के चंदन

किसान कर्म सिंह बताते हैं कि चंदन दो प्रकार के होते हैं। लाल और सफेद। लाल चंदन की खेती साउथ इंडिया में होती है। सफेद चंदन की खेती मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र होती है। लाल चंदन पर सांप आते हैं, जबकि सफेद चंदन पर सांप नहीं आते हैं। पेड़ की ऊंचाई 18 से लेकर 20 मीटर तक होती है।

200 पेड़ों से चार करोड़ रु. से ज्यादा की कमाई

आधे बीघा में चंदन के पौधे की नर्सरी भी है, जिसमें हर साल करीब 6 से 7 हजार पौधे तैयार करते हैं। इसे मध्यप्रदेश के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों को सप्लाई करते हैं। एक पौधा 200 रुपए में बिकता है। इसमें हर साल करीब 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तीन लाख की इनकम रुपए फल, फूल, पत्ती और टहनियों से हो जाती है। लागत हटाकर अभी हर साल 15 लाख रुपए की इनकम हो रही है। 6-7 साल बाद जब पेड़ 12 से 15 साल के हो जाएंगे तो कटने लायक हो जाएंगे। उस समय एक पेड़ से दो से ढाई लाख रुपए का मुनाफा होगा। सभी 200 पेड़ों से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होगी।

चंदन के पौधों के लिए खेत ऐसे तैयार करें

रोपाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेती की दो से तीन बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। अब पाटा लगाकर खेत को समतल बनाएं। इसके बाद खेतों में 10-10 फीट की दूरी पर 45 सेंटीमीटर चौड़े और उतने ही गहरे गड्ढे बना लें। इसके बाद गोबर खाद डालकर पौधे लगाएं। जहां पौधे लगा रहे हैं, वहां जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी से नुकसान होता है।

बीज से ऐसे बनाते हैं पौधे

किसान कर्म सिंह बताते हैं कि सबसे पहले चंदन के बीज को 24 घंटे पानी में डाल देते हैं। उसके बाद केमिकल डालते हैं। फिर बेड बनाकर डाल देते हैं। नेट लगा देते हैं। फिर पराली से ढक देते हैं। एक महीने बाद जर्मिनेशन हो जाता है। फिर एक महीने बाद ही पॉलिथीन में ट्रांसफर किया जाता है। उसके साथ एक बेल लगाई जाती है। फिर दो महीने इसमें रखते हैं। चार महीने के इस प्रोसेस में पौधे की हाइट करीब एक से डेढ़ फीट तक हो जाती है।

-सेंट्रल बैंकर्स कमेटी की बैठक में सचिव अलका बोलीं

भारत दूध उत्पादन में अग्रणी, अंडा-मछली में तीसरा और मुर्गी उत्पादन में पांचवां देश

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुपालन और डेयरी को क्षेत्र में देश को आगे ले जाने के लिए लहतार प्रयास किए जा रहे हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) के लिए केंद्रीय स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की पहली बैठक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए में निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने और संगठित प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बैंक लोन-लिंक्ड योजनाओं को देश में लागू करने पर चर्चा की गयी। डीएएचडी की सचिव अलका उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीएएचडी, नाबार्ड, सिडबी, एनडीडीबी, एनसीडीसी के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित ऋणदाता बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अलका उपाध्याय ने भारत के पशुधन क्षेत्र के विकास में बैंकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत दूध उत्पादन में अग्रणी देश, अंडा और मछली उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश और मांस और मुर्गी उत्पादन में पांचवां सबसे बड़ा देश है, ऐसे में आहार में इन उत्पादों को शामिल करने से प्रोटीन की कमी को दूर किया जा सकता है। भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने, निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने और संगठित प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बैंक लोन-लिंक्ड योजनाओं को लागू करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

विभिन्न पहलुओं के साथ चुनौतियों पर चर्चा

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ), राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम और किसान क्रेडिट कार्ड सहित डीएएचडी योजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। चर्चा में उपलब्धियां, दिशा-निर्देशों में संशोधन, पोर्टल का उपयोग, लंबित मुद्दे और लोन देने वाली संस्थाओं की भूमिका और अपेक्षित सहायता शामिल थी। कोलेटरल सेक्यूररिटी की कमी के कारण छोटे उद्यमियों के लिए वित्त तक सीमित पहुंच, पात्र परियोजनाओं को मंजूरी देने में देरी, ब्याज छूट दावों और सहायक दस्तावेजों को समय पर जमा न करना और उपस्थित ऋणदाताओं से फीडबैक जैसी चुनौतियों पर विशेष जोर दिया गया।

पशुपालन में बैंक की भूमिका अहम

वहीं, अतिरिक्त सचिव (मवेशी और डेयरी) वर्षा जोशी ने भारत के पशुपालन क्षेत्र को बदलने में ऋण देने वाली एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने विचार रखे। संयुक्त सचिव (एनएलएम) डॉ. ओपी चौधरी ने बैठक की शुरुआत की। अतिरिक्त संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मत्स्य पालन और प्रशासन) सागर मेहरा ने मत्स्य विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं का समर्थन करने में बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं की भूमिका पर जानकारी साझा की।

-मध्यप्रदेश यूपी, केरल और तमिलनाडू भी नहीं पीछे

देश के कई राज्यों में सबसे ज्यादा हो रही दूध में मिलावट

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में दूध की कोई कमी नहीं है। बीते साल ही 23 करोड़ टन से ज्यादा दूध का उत्पादन हुआ था। देश की दूध डिमांड पूरी करने के साथ स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में घी-मक्खन जैसे डेयरी प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जा रहे हैं। बावजूद इसके देश में नकली दूध बनाने वाला माफिया सक्रिय है। देश के दो-चार राज्यों को छोड़ दें तो देशभर में नकली दूध बनाने और मिलावट का कारोबार खूब फल-फूल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं हर रोज नकली दूध बनाने वालों को कार्रवाई होती है। आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाता है। यूपी में तो किसी भी तरह की मिलावट को अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। बावजूद इसके मिलावटी दूध का कारोबार सबसे ज्यादा यूपी में ही पकड़ा जा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक तीन ऐसे राज्य हैं जहां नकली दूध बनाने का कारोबार सबसे ज्यादा हो रहा है।

राज्यसभा में पेश रिपोर्ट से हुआ खुलासा

इतना ही नहीं, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी लगातार मिलावटी और नकली दूध के मामले पकड़े जा रहे हैं। हाल ही में परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट से खुलासा होता है कि देश में अभी भी नकली दूध बनाने का कारोबार चल रहा है। ये बात अलग है कि नकली दूध बनाने का काम किसी राज्य में छोटा तो कहीं बड़ा है। रिपोर्ट से ही खुलासा होता है कि बीते तीन साल में नकली दूध के सबसे ज्यादा मामले यूपी, केरल और तमिलनाडू में सामने आए हैं। अगर साल 2023-24 की बात करें तो यूपी में 16 हजार से ज्यादा दूध के सैम्पल पॉजिटिव पाए गए थे। मतलब फ्रेश दूध के जो मानक हैं उसे ये सैम्पल पूरा नहीं कर रहे थे। इसी तरह से तमिलनाडू में 22 सौ से ज्यादा मामले पकड़े गए थे। वहीं केरल में 13 सौ सैम्पल पॉजिटिव पाए गए थे। 2022-23 और 2021-22 में भी खासतौर पर इन्हीं तीन राज्यों में नकली और मिलावटी दूध के मामले सबसे ज्यादा पकड़े गए थे।

ज्यादा बरसात से चिंता में किसान सोयाबीन को हो सकता नुकसान

भोपाल। प्रदेश में अत्यधिक वर्षा को देखते हुए किसान सांसत में है। मौजूदा मौसम को देखते हुए इसमें धान से अधिक चिंता सोयाबीन को लेकर है। इधर कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों ने किसी तरह के बहुतायत नुकसान से इंकार किया है। इसके साथ ही व्यक्तिगत नुकसान पर किसानों को बीमा कंपनियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है। दरअसल एक जून से प्रदेश में अब तक 21 प्रतिशत बारिश अधिक हो चुकी है। छह अगस्त की स्थिति में पश्चिमी मप्र के मुकाबले पूर्वी मध्यप्रदेश में करीब छह प्रतिशत बारिश कम हुई है। बावजूद इसके औसत से ज्यादा हुई लगातार बरसात के कारण खेतों में पानी भर गया। इसकी निकासी नहीं होने से फसलों को नुकसान हुआ है। भारतीय किसान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने बताया कि हरदा, होशंगाबाद, विदिशा, इंदौर और उज्जैन जिलों में बरसात से सब्जी की फसल जहां खराब हो गई हैं। वहीं खेत में किसानों के कई हिस्से की धान व सोयाबीन के पौधे खराब होने की जानकारी सामने आई है।

व्यक्तिगत नुकसान है सामूहिक नहीं

इधर कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो अभी तक सामूहिक रूप से कृषि खराब होने की जानकारी सामने नहीं आई है। व्यक्ति रूप से किसानों द्वारा खेत के कुछ हिस्सों की फसल के नष्ट होने की शिकायतें जिला कार्यालयों तक जरूर पहुंचाई गई है। कृषि उपसंचालक सुमन प्रसाद ने भोपाल जिले को लेकर बताया कि जानकारी सामने आने पर किसानों को कृषि बीमा कंपनी से सीधे मोबाइल पर शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है।

जायज है किसानों की चिंता

कृषि विज्ञान महाविद्यालय रीवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिलेश पांडेय ने किसानों की चिंता को जायज बताते हुए खेत में पानी निकासी के समुचित प्रबंध की सलाह दी है। वहीं पौध रोग निदान लक्षण विद्या के वरिष्ठ विशेषज्ञ केएस बघेल ने बताया कि पानी ज्यादा गिरने और उसके बाद तापमान में बढोत्तरी नुकसानदेह ही है। मूंग, उड़द, सोयाबीन और अरहर की फसलें पीले रोग से संक्रमित हो सकती हैं। बता दें कि अभी फलियां नहीं आई है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)